दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

Govt. Registered Social Justice Union

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 02 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 126

बजट में किसानों को मिला तोहफा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया श्री अन्न योजना का ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट को पेश करते हुये इसे अमृत काल का पहला बजट बताया और कहा कि यह समग्र विकास का बजट है जिसके परिणाम सभी देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश है। सीतारमण ने यहां लोकसभा में बजट भाषण का शुभारंभ करते हुये कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है। इस आखिरी पूर्ण बजट में कृषि और किसानों पर जोर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए कृषि क्षेत्र और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं।

वित्त मंत्री ने कहा कि बाजरा, कोदो, सामा जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की जाएगी जिससे हम परंपरा में शामिल अच्छा स्वास्थ्य देने वाला भोजन कर सकें और दुनिया को भारत की परंपरा से अवगत करा सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करे और उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।

इसमें एग्रिकल्चर एक्सलरेटर फंड की स्थापना की बात कही। हॉर्टिकल्चर और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही सहकार से समृद्धि की भी बात कही। वित्त मंत्री ने 63,000 पैक्स के डिजिटाइजेशन के साथ-साथ पैक्स के लिए मॉडल बाईलॉज बनाने की भी बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जायेगी, जो किसानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होगा।

पहचान पत्र माना जाएगा पेन कार्ड, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा। अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है। कारोबार की शुरुआत भी पैन कार्ड से ही हो सकती है।

बता दें कि आयकर विभाग हर भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड जारी करता है। पैन की मदद से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता चलता है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फंड लेने और लोन के आवेदन के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी होता है।

पैन कार्ड को भारतियों के लिए एक पहचान पत्र के रूप में माना जाता है। कुछ कार्यों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है जैसे, इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फण्ड निवेश, लोन के अप्लाई करना और आदि। हालांकि, पैन कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य सभी की वित्तीय जानकारी रखना है ताकि टैक्स संबंधित लक्ष्य पूरे हो सकें।

पीएम आवास योजना के लिए बजट में इजाफा, 79 हजार करोड़ होंगे जारी- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान देश की जनता को किफायती घर मुहैया करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66 फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब ये बजट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है।

बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के सभी लोगों को अपना घर देना है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिनके पक्के घर नहीं हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर वित्त वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार से आवंटित किए जाते हैं। पात्रता की बात करें तो इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं। इसमें उन लोगों को घर दिया जाता है, जिनके पास पक्का मकान न हो। आवास योजना के तहत लिस्ट तैयार करते समय ये चेक किया जाता है कि लाभार्थी के पास कोई मोटर युक्त दुपहिया या तिपहिया वाहन तो नहीं है। इसके साथ ही अन्य कई मानक तय किए गए हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

खड़े ट्रक से टकराई बाइक , तीन युवकों की मौत

शहडोल (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बुढ़ार थाना क्षेत्र के रूंगटा तिराहा के पास गत दिवस एक बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई जिसमें सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था। बाइक अनियंत्रित होने से खड़े ट्रक के पीछे के हिस्से से टकराते हुए अंदर घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के एनसीसी कैडेटों को एनसीसी आरडी कैंप में चौथा स्थान हासिल

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एनसीसी कैडेटों ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न गणतंत्र दिवस एनसीसी कैंप में चौथा स्थान हासिल किया। सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गणतंत्र दिवस शिविर में देश के प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 17 एनसीसी निदेशालयों के दल शामिल होते हैं और इसमें कई प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं जिनमें पीएम रैली, वीवीआईपी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर और कर्तव्य पथ पर मार्च करना शामिल है। सांस्कृतिक प्रदर्शन क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुशासन और कैडेटों के रहने वाले क्षेत्र के रखरखाव को प्रदर्शित करता है। सेना ने कहा, एक समर्पित प्रशिक्षण टीम के तहत नगरोटा में लगभग पांच सप्ताह तक इस सबसे प्रतिष्ठित एनसीसी शिविर के लिए कैडेटों ने प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत की। कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के तीनों क्षेत्रों के 114 कैडेटों के अत्यधिक प्रेरित दल ने उत्कृष्ट सौहार्द विकसित किया और काम किया, जैसे एक एकजुट टीम। उनके साथ तीन सहयोगी एनसीसी अधिकारी और निदेशालय के एनसीसी बटालियन के सहायक कर्मचारी थे।

9वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, मौत

इंदौर (आरएनएस)। बाणगंगा में रहने वाली एक नौवीं की स्टूडेंट्स ने अपने घर में फांसी लगा ली। वह अपने से छोटे भाई व बहन को स्कूल छोड़कर आई थी। वहीं माता-पिता व बड़ी बहन घर पर नहीं थे। जब छोटे भाई-बहन स्कूल से लोटे तो उन्होंने बहन को फंदे पर लटके देखा। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक मृतिका का नाम निकिता (17) पुत्री मातादीन पटेरिया है। चचेरे भाई विशाल ने बताया कि वह घर के पास ही रहता है। दोपहर में उसे सूचना मिली कि निकिता ने सुसाइड कर लिया है। वह घर पहुंचा तो वह फंदे पर लटकी थी। उसे उतारकर अस्पताल लेकर आए। लेकिन डॉक्टरों ने यहां मृत घोषित कर दिया। निकिता नौवीं क्लास की स्टूडेंट्स थी। वह लॉकडाउन के बाद से स्कूल नहीं जा रही थी। उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। वहीं मां निजी कंपनी में नौकरी करती है। निकिता की एक बड़ी बहन भी है जो काम से बाहर गई थी। परिवार के लोगों के मुताबिक सुबह निकिता के छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं। वह उन्हें स्कूल छोड़कर घर पर आ गई थी। इसके बाद से वह अकेली थी। पुलिस के मुताबिक अभी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले में जांच की जा रही है।

दक्षिण ब्राजील में टूर बस पलटने से सात लोगों की मौत, दर्जनों घायल

साओ पाउलो । ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में इग्वाजु जलप्रपात जा रही एक बस के पलट जाने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गयी और 22 अन्य घायल हो गये। पुलिस के अनुसार पराना के संघीय राजमार्ग पर 54 लोगों को ले जाने वाली बस सांता कैटरिना राज्य की राजधानी फ्लोरियानोपोलिस से रवाना हुई थी, जो अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमा से लगे ब्राजील के शहर फोज डू इगुआकू के आगे दक्षिण की ओर जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वायाकाओ कैटरीनेंस कंपनी द्वारा संचालित बस राजमार्ग से दूर हो गई और फर्नांडीस पिनहेइरो के केंद्रीय पराना शहर में एक पहाड़ी से नीचे गिर गई। स्थानीय अग्निशमन विभाग ने संवाददाताओं को बताया कि मरने वालों में अर्जेंटीना की एक मां और उसकी तीन साल की बेटी शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक अन्य वाहन शामिल था। एक जीवित यात्री एलेक्जेंड्रो डी ओलिवेरा गमारो ने कहा कि उसने दुर्घटना के बाद बस चालक से बात की और चालक ने सो जाने की बात स्वीकार की।

मुरैना के पहाडगढ़ के जंगल में मिले सुखोई विमान के अवशेष

मुरैना (आरएनएस)। आसमान में टकराने के बाद क्रैश हुए मिराज और सुखोई विमान के हिस्सों की तलाश में चार दिन बाद भी वायुसेना पहाड़गढ़ के जंगल में सर्चिंग कर रही है। मिराज विमान के कुछ हिस्से अब भी जंगल में पड़े हैं, वहीं गत दिवस सर्चिंग के दौरान सुखोई विमान के भी कुछ हिस्से मिलने की जानकारी मिली है। 28 जनवरी को ग्वालियर स्थित सेना के एयरबेस से राउंटिग आपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन के तहत उड़े लड़ाकू विमान मिराज व सुखोई सुबह जिले के पहाड़गढ़ के जंगलों के ऊपर हवा में ही आपस में टकरा कर क्रैश हो गए। मिराज विमान आग का गोला बनकर पहाड़गढ़ के ईश्वरा महादेव के जंगलों में गिरा, जिसमें पायलट

विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी बलिदान हो गए थे। सुखोई विमान के दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर विजय पाटिल व मिथुल पीएम पैराशूट की मददसे पहाड़गढ़ के जंगल में उतर गए, जबकि इनका सुखोई विमान 90 किमी दूर राजस्थान के भरतपुर में जाकर गिरा था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट को मंजूरी दी

नई दिल्ली । आरएनएस

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के आम बजट को बुधवार को हुई बैठक में मंजूरी दे दी। बजट पेश किए जाने से पहले यहां संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए लोकसभा में पेश किए जाने वाले आम बजट को मंजूरी दी गई। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस बीच बजट की प्रतियां सुरक्षा व्यवस्था के बीच संसद भवन पहुंच गई हैं।

धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई

रांची (आरएनएस)। झारखंड के धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर की बगल में स्थित आशीर्वाद टावर में कल देर शाम आग लग गयी और जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई।

धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज बताया कि मृतकों में 10 महिला तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आग आशीर्वाद ट्विन टावर के पीछे वाले बी ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर लगी थी। दमकल की गाड़ियां रात में ही आग पर काबू पाने की कोशिश में सफल रही।

सूत्रों ने बताया कि शादी के

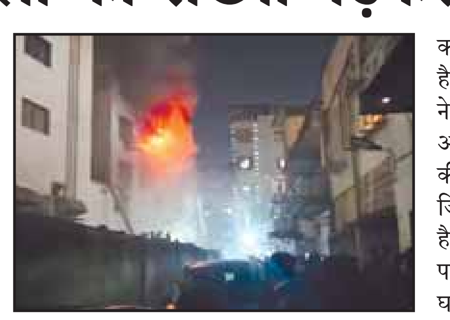

कार्यक्रम के लिए, लोग अपार्टमेंट में थे तभी गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई। आग दूसरे तल्ले में चार्टर्ड एकाउंटेंट पंकज अग्रवाल के घर लगी, जो धीरे धीरे तीसरे तल्ले तक फैल गई और इसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

इस बीच पीएमओ ने इस बात को लेकर दो ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धनबाद में आग लगने से कई लोगों की मौत की सूचना मिली जिससे मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धनबाद अग्निकांड में प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ की ओर से दो लाख रुपये दिये जाएंगे जबकि घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

त्रिपुरा : 16 फरवरी को मतदान के लिए 43 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात

अगरतला (आरएनएस)। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और राज्य पुलिस सहित 43,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) निष्पक्ष और हिंसा मुक्त विधानसभा चुनाव के लिए सीएपीएफ की 400 कंपनियां (30,000 सुरक्षाकर्मी) प्रदान करने पर सहमत हो गया है।

अधिकारी ने बताया कि सीएपीएफ के अलावा, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, लगभग 8,000 टीएसआर जवानों और 5,000 से अधिक त्रिपुरा पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीएपीएफ की 200 कंपनियां पहले ही त्रिपुरा आ चुकी हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात की जा चुकी हैं, जबकि फरवरी के पहले सप्ताह तक सीएपीएफ की 200 और कंपनियां आ जाएंगी।

अधिकारी ने कहा कि सीएपीएफ को क्षेत्र में वर्चस्व, गश्त, फ्लैग मार्च, वाहन गश्त, नाका ड्यूटी, छापेमारी के अलावा उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया था।

अधिकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा 18 जनवरी को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर कुल 192 नाका प्वाइंट (चेक गेट) स्थापित किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, सभी नाका बिंदुओं पर नाका जांच नियमित रूप से चल रही है। विशेष वाहन जांच भी चल रही है। वाहन जांच के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया और 11,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस, टीएसआर और सीएपीएफ की संयुक्त भागीदारी से अब तक 1,700 से अधिक फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग की जा चुकी है। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जो बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात हैं, न केवल अपनी निगरानी तेज करेंगे, बल्कि अपने समकक्षों बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश के साथ भी संपर्क में रहेंगे, ताकि भारत में अवैध प्रवेश को रोका जा सके।

उन्होंने कहा, बीएसएफ त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए अपने समकक्षों के साथ तुरंत बैठक बुलाएगा।

चुनाव आयोग के तीन विशेष पर्यवेक्षकों ने पांच दिनों के लिए त्रिपुरा का दौरा किया और 16 फरवरी की चुनाव तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

तीन विशेष पर्यवेक्षक कर्नाटक कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेंद्र त्रिपाठी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और आईआरएस अधिकारी बी. मुरली कुमार, जो गुजरात (2022) और पश्चिम बंगाल (2021) के विधानसभा चुनावों में विशेष पर्यवेक्षक थे।

अधिकारी ने कहा कि पर्यवेक्षकों ने निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो, मारिजुआना के बागानों और अन्य प्रवर्तन उपायों का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

86 मिनट के बजट भाषण में पीएम मोदी ने 100 से भी अधिक बार थपथपाई मेज

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में 86 मिनट तक अपना बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री के 86 मिनट के इस बजट भाषण के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज थपथपाकर अपने वित्त मंत्री का हौसला बढ़ाते और बजट घोषणाओं की सराहना करते नजर आए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुल 86 मिनट के बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 124 बार मेज थपथपा कर वित्त मंत्री द्वारा की जा रही बजट घोषणाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ बैठे सरकार के तमाम मंत्री, भाजपा सांसद और सहयोगी दलों के सांसदों ने भी बजट भाषण के दौरान लोक सभा में 124 बार मेज थपथपा कर बजट की सराहना की।

बजट भाषण के दौरान लोक सभा में भाजपा और कांग्रेस सांसदों के बीच नारे लगाने की भी होड़ दिखाई दी। बजट भाषण के दौरान सदन में कई बार भाजपा सांसद 'मोदी-मोदी' के नारे लगाते नजर आए, वहीं इसके जवाब में कांग्रेसी सांसद 'भारत जोड़ो' का नारा लगाते सुनाई दिए।

भाषण के दौरान ही विपक्षी बेंच की तरफ से कई बार टोकाटोकी भी हुई। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दो बार खड़े होकर पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ी कीमत का मुद्दा उठाया।

पूंजीगत व्यय 37.4 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि '' अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। निवेश और रोजगार सृजन के चक्र में तेजी लाने के लिए बजट ने एक बार फिर से संशोधित अनुमान 2022-23 में 7.28 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बीई 2023-24 में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि कर 10 लाख करोड़ रुपए के साथ पूंजीगत व्यय परिव्यय में तेज वृद्धि करने के द्वारा अग्रणी भूमिका निभाई है। राजकोषीय नीति के वक्तव्यों में रेखांकित किया गया है कि कैपेक्स वित्त वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय का लगभग तीन गुना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेल, रक्षा आदि जैसे प्रमुख अवसंरचना एवं रणनीतिक मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। वित्तीय नीति के अनुसार यह बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के माध्यम से अवसंरचना विकास पर सरकार के बल को बहुगुणित करता है।

इसमें देशभर में ऐसे निवेशों की इक्विटी और समानता सुनिश्चित करने की भी बात की कई है। यह अगले 25 वर्षों में 4 आई – इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनवेस्टमेंट, इनोवेशन और इनक्लूजन पर सरकार के फोकस और प्रतिबद्धता के अनुरूप है।सहकारी राजकोषीय संघवाद की भावना में राज्यों के हाथ मजबूत करने के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में आरंभ की गई स्कीम को 1.30 लाख करोड़ रुपए के बढ़े हुए परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2023-24 तक विस्तारित कर दिया गया है। यह बीई 2022-23 के आवंटन की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और वित्त वर्ष 2023-24 के जीडीपी का लगभग 0.4 प्रतिशत है। बजट में बताया गया है कि राजस्व व्यय के 34.59 लाख करोड़ की तुलना में 2023-24 में 1.2 प्रतिशत बढ़कर 35.02 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान, प्रमुख सब्सिडियां, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, और वित्त आयोग अनुदानों के रूप में राज्यों को हस्तांतरण, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं आदि शामिल हैं।किया गया अनुमानित ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ रुपये का रहा जो कुल राजस्व व्यय का 30.8 प्रतिशत है।

सब्सिडी- वित्तीय विवरण के अनुसार सब्सिडिज का राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण स्थान रहता है जिसमें भोजन, उर्वरक और पेट्रोलियम, सब्सिडी शामिल हैं। प्रमुख सब्सिडियां 3.75 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) हैं जो बजट अनुमान 2023-24 में राजस्व व्यय का 10.7 प्रतिशत है।

वित्त आयोग अनुदान- बजट के अनुसार राज्यों को राजस्व घाटा अनुदानों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान जैसी विविध श्रेणियों तथा अन्य निकायों को दिया गया कुल वित्त आयोग अनुदान वित्त वर्ष 2023 में 1.65 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

पेंशन- बजट अनुमान 2022-23 में व्यय 2.07 लाख रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान 2022-23 में बढ़कर लगभग 2.45 लाख करोड़ रुपए होने से व्यय में वृद्धि देखी गई। बजट अनुमान 2022-23 में इस बढ़ोत्तरी के पीछे मुख्य कारण रक्षाकर्मियों के संबंध में वन रैंक वन पेंशन के कारण देनदारियों को चुकाना रहा। बजट अनुमान 2023-24 में पेंशन भुगतान 2.34 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित जीडीपी का 0.8 प्रतिशत है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

कुल व्यय- वर्ष 2023-24 में वित्तीय नीति विवरण कुल व्यय 45.03 लाख करोड़ रुपए होने के बारे में जानकारी दी गई है जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 7.5 प्रतिशत अधिक है।